statement on 27th October, 1996 at Guwahati pertaining to new initiatives for NE region comprising programmes/schemes/projects for economic development of seven North-Eastern States. The estimated cost of the projects/schemes envisaged in the statement amounted to about Rs. 6100.00 crore.

(b) and (c) The details of progress of implementation of these programmes/schemes/projects, funds released and balance action required is given in the Annexure. (*See* Appendix 181, Annexure No. 71.)

Confining the role of Planning Commission

2611. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to confine the role of Planning Commission to a few sectors of activities that require detailed planning and delegate the responsibility of power for planning in regard to the remaining sectors to Central Ministries and States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The role of Planning Commission continue to remain same as given in the Resolution of the Cabinet Secretariat dated the 15th March, 1950 setting up the Planning Commission. However, the Approach Paper to the Ninth Plan envisage formulation and implementation of the Ninth Plan in the spirit of Cooperative Federalism which inter alia include greater role for the States in the formulation as well as implementation of the Plan Schemes. The Approach Paper also envisage preparation of detailed sectoral plans for certain sectors like power, selected medium and major irrigation projects, critical communication and agricultural development and infrastructure etc.

विश्व बैंक निधि का झारखण्ड क्षेत्र में दुरुपयोग

2612. श्री ज्ञान रंजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारखण्ड क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी निधियों का दुरुपयोग हो रहा है और यह कभी भी एक बड़े घोटाले के रूप में आ सकत है ;

(ख) क्या कुछ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े ठेकेदारों को ही काम मिलता है ;

(ग) क्या ये ठेकेदार 20 प्रतिशत शुद्ध मुनाफे पर छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम दे देते है ;

(घ) क्या काम करवाने के लिए नियमित निविदा मंगवायी जाती है, और जिनकी सबसे न्यूनतम दर होती है उन्हीं को काम दिया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार इन परिस्थितियों को देखते हुए इसकी जांच कराएगी और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (ङ) झारखण्ड प्राप्त स्कीमों का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा इनकी मानीटरिंग राज्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।